केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450] 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 202 गुरूवार 12 फरवरी 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

बजट में शिक्षा–स्वास्थ्य, कृषि पर विशेष जोर

लखनऊ (आभा)। योगी सरकार ने 9.12 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष जोर दिया गया है। स्वच्छताकर्मियों को सीधे 16–20 हजार रुपये मिलेंगे। किसानों के लिए सोलर पंप, एफपीओ फंड और एग्री एक्सपोर्ट हब की घोषणा हुई। राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत सीमा में रखा गया है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया। 'नव निर्माण के नौ वर्ष' की थीम पर प्रस्तुत बजट 2026–27 का कुल आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2025–26 की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। आकार के लिहाज से योगी सरकार ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को बताया कि यह बजट राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता, निवेश के अनुकूल माहौल और सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन का परिणाम है। यह बजट न केवल राज्य की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है, बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सतत विकास की स्पष्ट रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। बजट 2026–27 सरकार की उस सोच को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें विकास, वित्तीय अनुशासन और भविष्य की तैयारी तीनों को समान

महत्व दिया गया है। इस बजट में अन्नदाता किसान, युवा, महिला, छात्र–छात्राओं समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में 19.5 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो आधारभूत ढांचे, औद्योगिक विकास, सड़क, ऊर्जा और शहरी–ग्रामीण अधोसंरचना को नई गति देगा। पूंजीगत निवेश से रोजगार सृजन होगा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। योगी सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों को बजट में प्रमुख स्थान दिया है। इसके अंतर्गत शिक्षा के लिए कुल बजट का 12.4 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए 6 प्रतिशत और कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए 9 प्रतिशत का आवंटन किया गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार मानव संसाधन विकास और किसानों की आय बढ़ाने को विकास की धुरी मानकर चल रही है।

उन्होंने बताया कि 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026–27 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जो वर्ष 2030–31 तक लागू रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह राजकोषीय अनुशासन से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राजकोषीय घाटा 1,18,480.59 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.98 प्रतिशत है। यह 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर है और वित्तीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

समग्र परिप्रेक्ष्य में, बजट 2026–27 में एक ओर जहां विकासोन्मुख नई योजनाओं का विस्तार है, वहीं दूसरी ओर राजस्व बचत और नियंत्रित राजकोषीय घाटे के माध्यम से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का स्पष्ट प्रयास किया गया है।

बजट में विशेष रूप से कृषि विभाग के अंतर्गत डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की महत्वाकांक्षी योजना के लिए 637.84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों की डीजल पर निर्भरता कम होगी, लागत घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम कृषि क्षेत्र में हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनजर सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए रिवॉल्विंग फंड योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये का कोष नाबार्ड की सहभागी संस्था 'नैब किसान' के साथ मिलकर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें सरकार 75 करोड़ रुपये का अंशदान देगी।

एक नजर

कुआनो नदी से मिला युवक का शव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । लालगंज थाना क्षेत्र में बुधवार को कुआनो नदी के दबिला घाट पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

ग्राम पिपरा गौतम निवासी भरत सिंह पुत्र गोकुल सिंह ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया कि दबिला घाट, ग्राम लकड़ा (पुलिस चौकी महसो) के पास नदी में एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही लालगंज के प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम और चौकी प्रभारी महसो के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस के अनुसार, मृतक के हाथ पर 'दीपक' नाम का टैटू बना हुआ है। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि मृतक का नाम संभवतः दीपक है। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है और कस्बा महसो के राजा मैदान बाजार क्षेत्र में भीख मांगकर गुजारा करता था। वह पिछले करीब दस वर्षों से इसी क्षेत्र में रह रहा था।

स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि मृतक शराब का सेवन करता था। पुलिस अब मृतक के स्थायी पते की जानकारी जुटाने में लगी है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है, ताकि मृत्यु के सही कारणों का पता चल सके।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

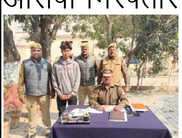

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। पैकोलिया पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित एक मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने की।

पुलिस के अनुसार, थाना पैकोलिया में दर्ज इस गंभीर मामले में आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता पाई।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान गफ्फार अली पुत्र अतीकुर्रहमान के रूप में हुई है। वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेल्डांगा थाना क्षेत्र के मझमपुर का निवासी है। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को बस्ती न्यायालय भेज दिया गया।

बहन की शादी से पहले भाई की हादसे में मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। हरैया–बभनान मार्ग पर मंगलवार रात एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा बहन की शादी से 10 दिन पहले हुआ। घटना बैरिहवा पेट्रोल टंकी के पास रात करीब 8.45 बजे हुई। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान गोंडा जिले के मसकनवा पोस्ट, ग्राम दुबौली भार्गव जोत निवासी सुनील कुमार वर्मा (30 वर्ष) पुत्र शिव कुमार वर्मा के रूप में हुई है। सुनील बहन की शादी का कार्ड रिश्तेदारों को बांटकर बाइक से घर लौट रहे थे। उनकी बहन की शादी 20 फरवरी को होनी थी।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल एनआईएलडी शासी परिषद सदस्य मनोनीत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। दिव्यांगता के क्षेत्र में निरन्तर कार्य कर रहे शिक्षित युवा सेवा समिति के निदेशक गोपाल कृष्ण अग्रवाल को राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांग जन संस्थान 'एनआईएलडी 'का शासी परिषद सदस्य मनोनीत किया गया है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल को विशेष न्याय एवं नवाचार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शासी परिषद सदस्य मनोनीत किये जाने पर विनोद कुमार उपाध्याय, पूनम सिंह , राम जी शुक्ला , राघवेन्द्र प्रताप मिश्र , अनुसूईया पाण्डेय , जीतेन्द्र श्रीवास्तव , राम

सुरेश , अमर सिंह, राकेश सोनी , शैलेश पाण्डेय , धीरेंद्र मोहन मिश्र , राजकुमार यादव , जवाहर लाल , पुष्पेष आर्या , आशीष पाण्डेय आदि ने प्रसन्नता व्यक्त किया है।

दबंगो ने मारा पीटा, घर पर कब्जे की कोशिशः एसपी से लगाया न्याय की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बंधुआ निवासी हजारी यादव पुत्र टिहुर ने निर्माणाधीन घर में जबरिया कब्जा करने की कोशिश, मारपीट कर जान से मार देने की धमकी देने, नल, पशुओं के चारा मशीन, हौदी, वा घर का दरवाजा तोड़कर घर का सामान, जेवरात उठा ले जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग किया है।

एसपी को दिये पत्र में हजारी यादव ने कहा है कि विगत 8 फरवरी को पड़ोसी पुजारी यादव पुत्र टिहुर यादव घर के नल, पशुओं के चारा मशीन, हौदी, वा घर का दरवाजा तोड़कर घर का सामान, जेवरात उठा ले गये। विकास यादव, छोटो पुत्री सीमा यादव, विपिन यादव, अमरनाथ यादव, नवीन यादव पुत्रगण पुजारी यादव, अभिषेक आदि ने मिलकर हजारी

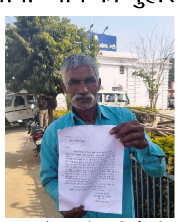

यादव को मारा पीटा। निर्माणाधीन घर में जबरिया कब्जा करने की कोशिश करते हुये भैस आदि ला कर बांध रहे हैं। थाने पर तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया। हजारी यादव ने मांग किया कि दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय और उसे न्याय दिलाया जाय।

समर्पण दिवस के रूप में याद किये गये पं. दीनदयाल उपाध्याय

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, बस्ती में बुधवार को संगठन के प्रेरणास्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर 'समर्पण दिवस' कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। उपस्थित नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने की। किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपेश्वर त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप 'एकात्म मानववाद' और 'अंत्योदय' के सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने राजनीति को नई दिशा देते हुए गाँव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित और आदिवासी समाज के उत्थान को सर्वोपरि माना। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र गौड़ ने पंडित जी के जीवन को सादगी, राष्ट्रसेवा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि उनके विचार आज भी संगठन और राष्ट्र निर्माण के लिए मार्गदर्शक हैं।

जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्थ्री इन वनश व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि वे एक समर्पित राजनेता, महान विचारक और कुशल संगठक थे। उन्होंने जोर दिया कि उनके सिद्धांतों को आत्मसात कर ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है।

इस अवसर पर यशकांत सिंह, दयाराम चौधरी, रवि सोनकर, संजय जायसवाल, चंद्रशेखर मुन्ना, प्रत्युष सिंह, गजेन्द्र सिंह, राम सिंगार ओझा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रहित में कार्य करने के संकल्प के साथ हुआ।

यूजीसी के नये नियमों को वापस लिये जाने की मांग को लेकर मेधा ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। यूजीसी के नये नियमों को वापस लिये जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। बुधवार को मेधा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीन दयाल त्रिपाठी के नेतृत्व में गांधी कला भवन के स्थित बापू प्रतिमा के निकट अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। दीन दयाल त्रिपाठी ने कहा कि जब तक यूजीसी का भेदभाव पैदा करने वाला कानून वापस नहीं लिया जाता मेधा चरणबद्ध आन्दोलन जारी रखेगी।

मेधा पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रूद्र आदर्श पाण्डेय ने कहा

कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा उच्च शिक्षा परिसरों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी नए नियमों के विरोध में आन्दोलन जारी रहेगा। कहा कि ये नियम उनकी पढ़ाई और भविष्य को प्रभावित करेंगे।

बापू प्रतिमा के निकट अनिश्चितकालीन धरना देने वालों में मुख्य रूप से उमेश पाण्डेय 'मुन्ना', नागेन्द्र मिश्र गुड्डू, गिरीश चन्द्र गिरी, प्रतीक मिश्र, अमरनाथ यादव, विपुल पाण्डेय आदि शामिल रहे।

ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को भेजा 7 सूत्रीय मांग पत्र

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । बुधवार को सिंचाई विभाग ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित 7 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन में संगणक से सहायक अभियन्ता ' सिविल' पद पर वर्षो से लम्बित उत्पन्न बाधाओं को दूर कराकर प्रोन्नति कराये जाने आदि की मांग शामिल है।

ज्ञापन में ड्राइंग संवर्ग के पदों का पुर्नगठन, अवर अभियन्ता की भांति ग्रेड पे इग्नोर कर वेतनमान दिये जाने, ड्राइंग संवर्ग के कार्मिको को अवर अभियन्ता सिविल /यांत्रिक के पद पर प्रोन्नत हेतु पृथक से कोटा निर्धारित किये जाने, ड्राइंग संवर्ग के पदों पर 1–1–1996 से व्याप्त वेतन विसंगति दूर किये जाने,

विभागीय प्रशिक्षण दिये जाने आदि की मांग शामिल है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष मस्तराम वर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष राम अधार पाल, मंत्री तौलू प्रसाद ने मांगों का समर्थन करते हुये कहा कि समस्याओं का प्रभावी निस्तारण कराया जाय। अन्यथा की स्थिति में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद संघर्ष करने को बाध्य होगा।

ज्ञापन देने के दौरान मुख्य रूप से सिंचाई विभाग ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन के मण्डलीय प्रभारी शीतल प्रसाद गुप्ता, सचिव संजय कुमार, बुद्धसागर यादव, दिनेश चन्द्र मिश्र, सुभाष चन्द्र, विजय सहाय, राजनरायन चौधरी, आशुतोष आर्या आदि शामिल रहे।

टेट अनिवार्यता को लेकर शिक्षको ने आदेश की प्रतियां जलाकर किया विरोध प्रदर्शनः केन्द्रीय मंत्री के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बीएसए कार्यालय पर शिक्षको ने टेट अनिवार्यता को लेकर आदेश की प्रति जलाकर उसका विरोध प्रदर्शन किया तथा सदन में सांसदों द्वारा टेट मुद्दे को लेकर उठाये गए प्रश्नों पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के जवाब को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

बड़ी संख्या में पहुचे शिक्षको ने बीएसए कार्यालय पर नारेबाजी की और सरकार के टेट मुद्दे पर गंभीरता को न लेने पर नाराजगी व्यक्त की है। जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह ने बताया कि लगातार संसद में 25 से अधिक पक्ष व विपक्ष के सांसदों ने दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाया था और सभी मानक और परीक्षाओं को पूर्ण कर नौकरी कर रहे शिक्षको पर अचानक टेट परीक्षा पास करने के अव्यवहारिक आदेश पर केंद्रीय मंत्री के लिखित बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, केंद्रीय मंत्री द्वारा सभी शिक्षको को टेट देने व परीक्षा पास करने की बात कही है, जबकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिला और उन्होंने भी पूर्ण आश्वासन दिया था कि संसद सत्र में इस प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।

–शिक्षक दिल्ली धरने की तैयारी में

जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा ने कहा कि सरकार यदि टेट मुद्दे पर सरकार ने कोई निर्णय नही लिया तो 25 लाख शिक्षको के रोजी रोटी पर संकट आ जायेगा और शिक्षक संगठन अब आर पार की लड़ाई लड़ने को भी तैयार है।

तहसील अध्यक्ष प्रताप नारायण चौधरी व राजकुमार तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली में लगातार धरने की रणनीति बना रहा है,विगत दिनों में दो बार दिल्ली धरने को लेकर सरकार में अनुमति देने के बाद वापस ले ली।लाखो शिक्षक दिल्ली कूच के लिए तैयार है और अपनी बातों को सरकार तक बजट सत्र में रखेगी।

महिला शिक्षिकाओ का पक्ष रखते हुए जिला संगठन मंत्री सविता पाण्डेय, रेहाना परवीन ने बताया कि 20 से 35 साल से शिक्षिका नौकरी कर रही है और जब नौकरी में आये तो सभी मानक और परीक्षा देकर नौकरी प्राप्त की और अब अचानक से अब परीक्षा पास करने का दबाव बनाया जा रहा है जिससे नौकरी भी अब खतरे में है। बड़ी संख्या में महिला शिक्षको ने विरोध प्रदर्शन किया।प्रदर्शन करने वालो में अशोक यादव, रामभवन, मोहम्मद असलम, नीरज सिंह, बब्बन पाण्डेय, रवि सिंह, रामसागर वर्मा, अखिलेश पाण्डेय, प्रताप नारायण, उमाकांत शुक्ल, मंगला मौर्य, देवेंद्र यादव, संतोष पाण्डेय, अनीस अहमद, रामपियारे, वीरेंद्र शुक्ला, गणेश श्रीवास्तव, तफ्फजूल, विवेक सिंह, मनोज उपाध्याय, हरेंद्र यादव, रुकनुद्दीन, सुनील, वेद उपाध्याय, विजय यादव, प्रमोद सिंह, प्रभात वर्मा, बृजेश त्रिपाठी, मंगला मौर्य, संजय यादव, नवीन सिंह, संजय चौधरी, कमर खलील, हरदीप,नीतू सिंह, शत्रुजीत यादव, सुषमा, उर्मिला चौधरी, शेषमणि पटेल उपस्थित रहे।

एड्स जागरूकता, प्रशिक्षण कार्यशाला में दिया जानकारी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उ.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ के निर्देशानुसार विकास खण्ड बहादुरपुर में मेनस्ट्रीमिंग के अंतर्गत एच आई वी, एड्स पर उन्मुखीकरण कार्यशाला एवं एड्स जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एचआईवी, एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना, संक्रमण से बचाव, समय पर जांच तथा उपचार सेवाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना रहा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला क्षय रोग अधिकारी बस्ती द्वारा नामित रिसोर्स पर्सन अम्बुज कुमार यादव द्वारा एचआईवी, एड्स संक्रमण के कारण एवं फैलाव, संक्रमण से बचाव के उपाय, समय पर एचआईवी जांच का महत्व, उपचार एवं परामर्श सेवाओं की उपलब्धता, एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के प्रति सामाजिक भेदभाव समाप्त करने की आवश्यकता की विस्तार से जानकारी दिया गया।

कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका, आंगनबाड़ी

कार्यकत्री, एएनएम, आशा बहुओं, ब्लॉक स्तरीय सुपरवाइजर, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों तथा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन बैचों मे विकास खंड राम नगर, विकास खंड रुधौली एवं विकास खंड बहादुरपुर मे सम्पन्न किया गया तथा प्रत्येक बैच में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग कर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

रिसोर्स पर्सन अम्बुज कुमार यादव ने कहा कि एचआईवी, एड्स जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। सही जानकारी एवं सामुदायिक सहयोग के माध्यम से संक्रमण की रोकथाम संभव है। समाज को इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गोविंद ने बताया कि एचआईवी संक्रमण से बचाव संभव है, नियमित जांच एवं परामर्श अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, संक्रमित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार आवश्यक है

कार्यशाला को सफल बनाने में जिला क्षय रोग अस्पताल के टीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर संदीप श्रीवास्तव, डीपीसी मोहम्मद सईद, मोहम्मद सऊद, मोहम्मद अफजल, शिव शंकर, ग्रामीण विकास सेवा समिति के मोहम्मद अशरफ, सानू गुप्ता, सुभेनद्र पाठक, रमाकांत आदि की अहम भूमिका रही इनके द्वारा टीबी और एच आई वी के संबंध को गहन से सभी के समक्ष रखा और जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने अपने–अपने कार्य क्षेत्रों में एचआईवी, एड्स जागरूकता संदेश को जन–जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेंडेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 12 फरवरी 2026 गुरूवार

सम्पादकीय

यूपी के बजट की दिशा दृष्टि

उत्तर प्रदेश सरकार का 2026–27 का बजट केवल अगले वित्त वर्ष की आय–व्यय योजना नहीं है, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की सबसे ठोस राजनीतिक पटकथा के रूप में देखा जा रहा है। 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये के इस बजट के जरिए सरकार ने यह साफ संकेत दिया है कि वह चुनाव से पहले विकास, सुरक्षा और कल्याण तीनों मोर्चों पर अपने दावों को आंकड़ों के साथ जमीन पर उतारकर पेश करना चाहती है। पिछले बजट के मुकाबले करीब 12.9 प्रतिशत बढ़े इस आकार को सत्ता पक्ष "विश्वास का बजट" बता रहा है, जबकि इसके भीतर छिपा राजनीतिक संदेश यह है कि सरकार न तो संसाधनों की कमी से जूझ रही है और न ही चुनाव से पहले खर्च बढ़ाने से पीछे हट रही है।

सरकार ने सबसे पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपने मजबूत पक्ष के रूप में सामने रखा है। 2024–25 के त्वरित अनुमान के अनुसार 30.25 लाख करोड़ रुपये की जीएसडीपी और 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर यह दिखाने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश अब केवल जनसंख्या वाला राज्य नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन चुका है। 2016–17 में जहां जीएसडीपी करीब 12.75 लाख करोड़ रुपये थी, वहीं आठ–नौ वर्षों में इसके ढाई गुना से अधिक होने को सरकार स्थिर शासन और निवेश के अनुकूल माहौल का नतीजा बता रही है। 2027 के चुनाव में यह आंकड़ा खासतौर पर शहरी मतदाताओं, कारोबारियों और निवेश से जुड़े वर्गों के सामने रखा जाएगा, ताकि यह संदेश जाए कि सत्ता में बदलाव विकास की रफ्तार को रोक सकता है।

प्रति व्यक्ति आय को लेकर दिए गए आंकड़े भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं। 2016–17 में 54,564 रुपये रही प्रति व्यक्ति आय के 2024–25 में बढ़कर 1,09,844 रुपये होने और 2025–26 में इसके 1,20,000 रुपये तक पहुंचने के अनुमान को सरकार आम आदमी की जिंदगी से जोड़कर पेश कर रही है। यह संदेश खास तौर पर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए है, जो महंगाई, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य खर्च को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। सरकार का दावा है कि आय बढ़ने का मतलब सिर्फ आंकड़ों में सुधार नहीं, बल्कि उपभोग और जीवन स्तर में बदलाव है।

गरीबी के मोर्चे पर 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का दावा 2027 के लिहाज से सबसे बड़ा सामाजिक कार्ड माना जा रहा है। मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत कार्ड, शौचालय और बिजली कनेक्शन जैसी योजनाओं से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों को एक साथ रखकर सरकार यह दिखाना चाहती है कि गरीब सिर्फ योजनाओं का नाम नहीं, बल्कि सत्ता की राजनीति का केंद्र है। चुनावी रणनीति में यह वर्ग इसलिए अहम है क्योंकि यह सीधे सरकार से जुड़ाव महसूस करता है और उसके फैसले अक्सर स्थिर रहते हैं।

रोजगार को लेकर बजट में पेश किए गए आंकड़े विपक्ष के सबसे मजबूत मुद्दे का जवाब माने जा रहे हैं। बेरोजगारी दर 2.24 प्रतिशत बताकर सरकार यह दावा कर रही है कि प्रदेश में रोजगार की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। पुलिस विभाग में 2017 से अब तक 2 लाख 19 हजार से अधिक भर्तियां, 1 लाख 58 हजार पदोन्नतियां, 60 हजार से ज्यादा प्रशिक्षणाधीन जवान और 83 हजार से अधिक पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को एक साथ जोड़कर सरकार यह दिखाना चाहती है कि सरकारी नौकरियां सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहीं। शिक्षा क्षेत्र में 34 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति भी इसी दिशा में रखा गया कदम है, क्योंकि शिक्षक समुदाय ग्रामीण और कस्बाई राजनीति में राय बनाने की अहम भूमिका निभाता है।

युवाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की रणनीति भी बजट में साफ दिखती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बिना गारंटी और बिना ब्याज ऋण देकर हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका राजनीतिक मतलब यह है कि सरकार उन युवाओं को भी साधना चाहती है, जिन्हें सरकारी नौकरी की सीमित सीटों से निराशा हुई है। अगर यह योजना आंशिक रूप से भी सफल होती है, तो 2027 तक लाखों परिवार सीधे इससे जुड़ सकते हैं।

कृषि क्षेत्र के आंकड़े ग्रामीण राजनीति को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। 3 लाख 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र में सरकार का सबसे मजबूत चुनावी हथियार माना जा रहा है। गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से करीब 3000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लाभ का दावा किसानों को यह याद दिलाने के लिए है कि भुगतान सीधे खाते में पहुंचा है। गेहूं, धान और मोटे अनाज की लाखों मीट्रिक टन खरीद और हजारों करोड़ रुपये के भुगतान के आंकड़े न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश हैं। नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था ग्रामीण मतदाताओं के लिए सीधा संदेश है कि सिंचाई लागत सरकार उठाने को तैयार है।

महिलाओं को लेकर बजट में दिए गए आंकड़े 2022 के चुनावी अनुभव से निकले हुए माने जा रहे हैं, जहां महिला मतदाताओं का झुकाव निर्णायक साबित हुआ था। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत 26.81 लाख बालिकाओं को लाभ, सेफ सिटी परियोजना, महिला पुलिस बीट, सीसीटीवी नेटवर्क और वर्किंग वूमेन हॉस्टल जैसे प्रावधान यह दिखाते हैं कि सरकार महिला सुरक्षा और सम्मान को केवल कानून–व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दा मानती है। महिला मतदाता भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों आधारों पर निर्णय करती हैं, और बजट में यह संदेश उसी दिशा में जाता है।

कानून–व्यवस्था से जुड़े आंकड़े भी 2027 की चुनावी कहानी का अहम हिस्सा हैं। डकैती, लूट, हत्या और अपहरण जैसे अपराधों में 40 से 80 प्रतिशत तक कमी के दावे के जरिए सरकार यह स्थापित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश अब पहले जैसा असुरक्षित नहीं है। पुलिस भवनों, आवास और संसाधनों पर हजारों करोड़ रुपये के प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। यह संदेश शहरी मतदाताओं, व्यापारियों और महिलाओं के लिए खास तौर पर अहम है।

कुल मिलाकर 2026–27 का बजट एक ऐसा दस्तावेज बनकर सामने आया है, जिसमें हर बड़ा आंकड़ा 2027 के मतदाता को ध्यान में रखकर चुना गया है। विकास, कल्याण, सुरक्षा और पहचान चारों को जोड़कर सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि सत्ता की निरंतरता ही स्थिरता की गारंटी है। आने वाले महीनों में यही बजट गांव–गांव, शहर–शहर होने वाली राजनीतिक बहसों का आधार बनेगा, जहां सरकार इन आंकड़ों के सहारे भरोसा मांगेगी और विपक्ष इन्हीं आंकड़ों को चुनौती देने की कोशिश करेगा।

एप्सटिन फाइल्स : शर्म, सन्नाटा और हमारी सामूहिक विफलता

—डॉ. सत्यवान सौरभ—

इतिहास के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब सभ्यता अपने ही आईने में झाँकने से डरने लगती है। आज हम ठीक उसी मोड़ पर खड़े हैं। जिन कांडों का खुलासा हो रहा हैकृजिनके वीडियो, दस्तावेज और गवाह सार्वजनिक हो चुके हैंकृवे महज अपराध नहीं हैं, बल्कि मानवता के विरुद्ध सुनियोजित, संरक्षित और सत्ता–समर्थित हमले हैं। इन घटनाओं की भयावहता इतनी गहरी है कि शब्द भी लड़खड़ा जाते हैं। फिर भी समाज इन्हें "कंटेंट" की तरह उपभोग कर रहा हैकृचाव, रोमांच और क्षणिक घृणा के साथकृऔर फिर अगली सनसनी की ओर बढ़ जाता है।

यह कोई नई कहानी नहीं है। हर बड़े घोटाले, हर सामूहिक अपराध के बाद यही क्रम दोहराया गया हैकृपहले इनकार, फिर आंशिक स्वीकारोक्ति, उसके बाद माफी या इस्तीफा, और अंततः "कम्पैरिटिवली बेहतर" का आत्मसंतोष। मानो न्याय कोई तुलनात्मक पैमाना हो, जहाँ कम बुरा होना ही अच्छा होने का प्रमाण बन जाए। पर असली सवाल कहीं गहरा हैकृजब अपराध हो रहे थे, तब आत्मा कहाँ थी? क्या नैतिकता केवल कैमरों के सामने ही जागती है? इन कांडों की सबसे भयावह परत सत्ता से जुड़ी है। उच्चतम पदों पर बैठे लोगकृजिन्हें समाज ईश्वरतुल्य मानता है जब दोषियों से संवाद करते, उन्हें संरक्षण देते, उनसे लाभ लेते या उनके लिए रास्ते बनाते पाए जाते हैं, तब लोकतंत्र की बुनियाद हिल जाती है। यह व्यक्तिगत नैतिक पतन नहीं, बल्कि संस्थागत अपराध है। क्योंकि जब अपराध को व्यवस्था का संरक्षण मिलता है, तब वह अपवाद नहीं रहता वह एक प्रणाली बन जाता है।

मीडिया की भूमिका यहाँ निर्णायक होनी चाहिए थी। लेकिन अक्सर वह भी दो ध्रुवों में बँटी नजर आती हैकृ एक ओर सनसनी, दूसरी ओर चुप्पी। सनसनी पीड़ितों की गरिमा को रौंदती है, जबकि चुप्पी अपराधियों को समय और सुरक्षा देती है। टीआरपी, क्लिक और ट्रेंड की दौड़ में सत्य दम तोड़ देता है। नतीजा यह कि जनता को तथ्य नहीं, भावनात्मक झटके मिलते हैंकृऔर झटकों से स्थायी सामाजिक कार्रवाई कभी जन्म नहीं लेती।

कानून और जाँच एजेंसियों की स्थिति भी कोई आश्वस्ति नहीं देती। धीमी जाँच, अधिकार–क्षेत्र की उलझनें, राजनीतिक दबाव और अंतहीन प्रक्रियाएँकृये सब मिलकर न्याय को टालने की एक सुव्यवस्थित मशीन बना देते हैं। कहा जाता है कि न्याय में देरी, न्याय से इनकार के समान होती हैय यहाँ यह कहावत एक कड़वी सच्चाई बनकर सामने आती है। पीड़ित थक जाते हैं, गवाह डर जाते हैं और अपराधी समय के साथ और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। सबसे असहज प्रश्न फिर भी आम जनता से जुड़ा है। क्या सचमुच हमें लकवा मार गया है? या हमें इस तरह ढाला गया है कि हम क्रोधित तो हों, पर संगठित न हो सकें? सोशल मीडिया हमें आवाज देता है, लेकिन दिशा नहीं। हम पोस्ट करते हैं, साझा करते हैं, गालियाँ देते हैं और यह मान लेते हैं कि हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। वास्तविक दुनिया में उतरने का धैर्य, जोखिम और निरंतरताकृये सब दुर्लभ होते चले गए हैं।

यह भी एक सच है कि जनता को थकाने की बाकघयदा रणनीति अपनाई जाती है। सूचनाओं की बाढ़, विरोधाभासी दावे, फर्जी खबरें और आधे–अधूरे सचकृइन सबके जरिये भ्रम पैदा किया जाता है। और भ्रम से निष्क्रियता जन्म लेती है। निष्क्रिय समाज अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित वातावरण होता है। कुछ देशों में माफियाँ माँगी जा रही हैं, कहीं इस्तीफे दिए जा रहे हैं और इन्हें बड़ी उपलब्धि की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन माफी तभी मायने रखती है जब उसके साथ जवाबदेही होकृकघनूनी कार्रवाई, संपत्ति की जब्ती, नेटवर्क का खुलासा और स्थायी संस्थागत सुधार। केवल चेहरे बदल देने से व्यवस्था नहीं बदलती। इस्तीफा न्याय नहीं है, वह अधिकतम उसकी शुरुआत हो सकता है।इस पूरे परिदृश्य में सबसे अधिक उपेक्षित पक्ष पीड़ितों का है। उनकी कहानियाँ, उनका दर्द और उनका पुनर्वासकृसब कुछ हाशिये पर धकेल दिया जाता है। जबकि न्याय का अर्थ केवल सजा नहीं हैय न्याय का अर्थ है पीड़ित की जिंदगी को दोबारा खड़ा करना। काउंसलिंग, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और गवाह सुरक्षाकृये सब उतने ही आवश्यक हैं जितनी अदालत की कार्यवाही। इनके बिना न्याय हमेशा अधूरा रहेगा।

तो रास्ता क्या है? प्रतिशोध नहीं। हिंसा की कामना हमें उन दरिंदों से अलग नहीं बनाती जिनसे हम घृणा करते हैं। सभ्यता की जीत क्रूरता से नहीं, बल्कि जवाबदेही से होती है। इसके लिए कुछ बुनियादी बिंदुओं पर समाज को एकजुट होना होगा।

पहला, स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय जाँच, क्योंकि सीमा–पार और सत्ता–समर्थित अपराधों में केवल राष्ट्रीय एजेंसियाँ पर्याप्त नहीं होतीं। दूसरा, पूर्ण प्रकटीकरणकृनाम, पद, नेटवर्क और वित्तीय लेन–देन का सार्वजनिक खुलासा। तीसरा, कघनूनी सुधारकृविशेष अदालतें, समयबद्ध सुनवाई और मजबूत गवाह सुरक्षा कघनून। चौथा, जिम्मेदार मीडिया, जो पीड़ित–केंद्रित, तथ्यपरक और निरंतर रिपोर्टिंग करे। पाँचवाँ, नागरिक एकजुटताकृशांतिपूर्ण, संगठित और लगातार दबाव। क्योंकि बदलाव किसी एक पोस्ट से नहीं, बल्कि निरंतरता से आता है।

अंततः यह लड़ाई नैतिकता की है। हर समाज को कभी न कभी यह तय करना पड़ता है कि वह सुविधा चुनेगा या सत्य। सुविधा हमें सुला देती है, जबकि सत्य हमें बेचैन करता है और इतिहास हमेशा उसी बेचौनी से आगे बढ़ता है। लानत दरिंदों पर तो बनती है। लेकिन इतिहास हमें इस आधार पर परखेगा कि क्या हमने अपने आक्रोश को क्षणिक नफरत में गँवा दिया, या उसे परिवर्तन की संगठित ताकघ्त में बदला। चुप्पी अब विकल्प नहीं है। देर से सही, पर न्याय आना चाहिएकृऔर ऐसा न्याय, जो केवल दोषियों को दंडित न करे, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित बनाए।यही इस समय की सबसे बड़ी माँग है। और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी।

क्यों गायब हो रहे हैं बच्चे?

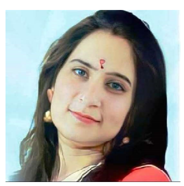

—डॉ. प्रियंका सौरभ—

हरियाणा में गुमशुदगी के बढ़ते मामले अब केवल पुलिस रजिस्टरों या अखबारों की सुर्खियों तक सीमित नहीं रहे हैं। ये मामले उन हजारों परिवारों की अनकही पीड़ा हैं, जिनके घरों से कोई सदस्य काम, पढ़ाई या रोजमर्रा के काम के लिए निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। हर दिन औसतन 12 बच्चों का लापता होना और वर्ष 2025 में 17,500 से अधिक गुमशुदगी के मुकदमों का दर्ज होना, किसी भी संवेदनशील समाज के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए। यह स्थिति न सिर्फ कानून–व्यवस्था की चुनौती है, बल्कि सामाजिक ताने–बाने पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।

गुमशुदगी का सबसे भयावह पहलू यह है कि इसके पीछे अब केवल व्यक्तिगत विवाद, घरेलू कारण या आकस्मिक घटनाएं नहीं रहीं। जांच में बार–बार यह संकेत मिल रहे हैं कि कई मामलों की जड़ें मानव तस्करी जैसे संगठित अपराधों से जुड़ी हुई हैं। पुलिस के अनुसार करीब 75 प्रतिशत मामलों को ट्रेस कर लिया गया है, लेकिन शेष 25 प्रतिशत अधूरे मामले ही असली चिंता का कारण हैं। यही वे मामले हैं जिनमें लापता व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिलता और जिनके पीछे अंतरराज्यीय गिरोह, अवैध प्लेसमेंट एजेंसियां और आर्थिक शोषण के नेटवर्क काम कर रहे होते हैं।

विशेष चिंता इस बात की है कि महिलाएं और नाबालिग बच्चे इस संकट का सबसे बड़ा शिकार बन रहे हैं। बेहतर रोजगार, उज्ज्वल भविष्य या शिक्षा का सपना दिखाकर बच्चों और युवाओं को उनके घरों से दूर ले जाया जाता है। कई बार माता–पिता खुद मजबूरी में बच्चों को ऐसे एजेंटों के हवाले कर देते हैं, जिन्हें वे भरोसेमंद समझते हैं। बाद में वही भरोसा परिवारों के लिए जीवनभर का पछतावा बन जाता है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों से जुड़े नेटवर्क इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह समस्या स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर फैले संगठित अपराध का हिस्सा है।

हरियाणा में भिक्षावृत्ति और बालश्रम से मुक्त कराए गए 350 से अधिक बच्चों के मामले इस सच्चाई को और उजागर करते हैं। चौक–चौराहों, बस अड्डों और धार्मिक स्थलों पर दिखाई देने वाले ये बच्चे किसी संयोग का परिणाम नहीं हैं। ये एक सुनियोजित तंत्र के तहत यहां लाए जाते हैं, जहां उनसे काम कराया जाता है या उन्हें भिक्षावृत्ति में धकेला जाता है। इनसे होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा गिरोह या प्लेसमेंट एजेंसियों के पास चला जाता है, जबकि बच्चों को अमानवीय परिस्थितियों में जीने को मजबूर किया जाता है।

यह भी गौर करने योग्य है कि मानव तस्करी अब अकेला अपराध नहीं रहा। पुलिस और जांच एजेंसियों का मानना है कि नशा तस्करी, साइबर अपराध, एक्सटॉर्शन और मानव तस्करी जैसे अपराध अब एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ही नेटवर्क कई तरह के अवैध कामों को अंजाम दे रहा है। यही कारण है कि गुमशुदगी के मामलों की जांच अब संगठित अपराध के नजरिये से की जा रही है। यह बदलाव सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन इसके लिए संसाधनों, तकनीक और राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी उतनी ही जरूरत है।

हरियाणा पुलिस द्वारा वर्ष 2026 के लिए तैयार किया गया अपराध नियंत्रण रोडमैप उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाता है। संगठित अपराधियों पर कड़ी निगरानी, तकनीक के माध्यम से पहचान और ट्रैकिंग, अंतरराज्यीय समन्वय और समयबद्ध जांच जैसे कदम निस्संदेह आवश्यक हैं। पुलिस महानिदेशक का यह स्पष्ट संदेश कि बच्चों और महिलाओं से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भरोसा पैदा करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल प्रशासनिक सख्ती से इस गहरी समस्या को पूरी तरह सुलझाया जा सकता है?

सच्चाई यह है कि गुमशुदगी और मानव तस्करी जैसी समस्याएं केवल कानून–व्यवस्था के दायरे में सुलझने वाली नहीं हैं। इनके पीछे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसे कारण भी काम करते हैं। जब परिवारों के पास रोजगार के सीमित अवसर होते हैं और बेहतर जीवन का सपना उन्हें हर दिन बेचैन करता है, तब वे अक्सर गलत हाथों में फंस जाते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि उन परिस्थितियों को बदलने की भी होनी चाहिए, जो लोगों को असुरक्षित बनाती हैं।समाज की भूमिका यहां सबसे अहम हो जाती है। अक्सर लोग लापता बच्चों या संदिग्ध गतिविधियों को देखकर भी चुप रह जाते हैं। "यह किसी और का मामला है" जैसी सोच अपराधियों के हौसले बढ़ाती है। यदि समय रहते संदिग्ध प्लेसमेंट एजेंसियों की सूचना दी जाए, भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों को नजरअंदाज न किया जाए और लापता होने की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाई जाए, तो कई मामलों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है। जागरूक समाज ही किसी भी अपराध के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन सकता है।

बाल अधिकार विशेषज्ञों का यह कहना बिल्कुल सही है कि बच्चों को तस्करी से मुक्त कराना केवल पहला कदम है। असली चुनौती उनके पुनर्वास, शिक्षा और मानसिक काउंसलिंग की है। तस्करी का शिकार हुए बच्चे गहरे मानसिक आघात से गुजरते हैं। यदि उन्हें समय पर सही देखभाल और अवसर नहीं मिले, तो वे दोबारा उसी अंधेरे चक्र में फंस सकते हैं। सरकार और समाज दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और सम्मानजनक हो।

हरियाणा में गुमशुदगी के मामले हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि विकास और आर्थिक प्रगति के दावों के बीच कहीं हम मानवीय मूल्यों को तो नहीं खोते जा रहे। यह समस्या केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि हर उस परिवार की कहानी है, जो आज भी किसी दरवाजे की आहट पर उम्मीद लगाए बैठा है। यदि अब भी इसे केवल एक खबर या एक प्रशासनिक चुनौती समझकर नजरअंदाज किया गया, तो आने वाले वर्षों में इसकी कीमत कहीं ज्यादा भारी होगी। समय की मांग है कि गुमशुदगी को अपराध के साथ–साथ मानवीय संकट के रूप में देखा जाए। सरकार, पुलिस, समाज और नागरिककृसभी को अपनी–अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तभी यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई बच्चा, कोई महिला या कोई नागरिक यूं ही गुम न हो जाए और उसका परिवार जिंदगी भर इंतजार करने को मजबूर न रहे।

कौन संत कौन 'असंत' ?

—निर्मल रानी—

कहने को तो 'बांटो और राज करो ' की नीति अंग्रेजों की बनाई हुई थी। परन्तु आज सत्ता हासिल करने के लिये या सत्ता में बने रहने के लिये यही नीति लगभग दुनियाभर के राजनीतिज्ञों द्वारा अपनाई जा रही है। जाहिर है हमारा देश और यहाँ की राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। और कहना गलत नहीं होगा कि 'बांटो और राज करो' की नीति का अनुसरण भले ही मौका मिलने पर सारे ही दल क्यों न करते हों परन्तु देखा यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी व इसकी सरकारों को इस मामले में कुछ ज्यादा ही महारत हासिल है। आप देखिये कि स्वयं को मजबूत व विपक्ष को कमजोर करने के लिये विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस के कितने ही नेता भाजपा ने अपने पाले में कर लिये। चाहे वह भ्रष्टाचार का आरोपी हो,आरोपी हो,अपराधी हो या भ्रष्ट हो परन्तु भाजपा में शामिल होते ही उसे 'मिस्टर क्लीन' का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। ऐसे कितने ही भ्रष्ट लोग आज मंत्री सांसद व विधायक यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक बने हुए हैं।

इसी तरह जब भारत में इतिहास का सबसे प्रमुख किसान आंदोलन 9 अगस्त 2020 से 11 दिसंबर 2021 तक चला था जिसमें केंद्र सरकार के तीन विवादित कृषि कानूनों के विरोध में देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे। उस समय भी भाजपा सरकार ने तरह तरह के हथकंडे अपनाये थे। उनमें एक हथकंडा किसान आंदोलन में शामिल संयुक्त किसान मोर्चा में शामिलकिसान संगठनों में फूट डालना भी शामिल था। चूँकि इस आंदोलन में पंजाब व हरियाणा के सिख बड़ी संख्या में शामिल थे इसलिये भाजपा सरकार के कई मंत्रियों ने इसे 'खालिस्तानी समर्थक' आंदोलन बताने की भी कोशिश की। परन्तु किसानों की एकजुटता के आगे यह सरकारी एजेंडा फुस्स हो गया। याद कीजिये जब कभी सत्ता के खिलाफ देश की विशिष्ट हस्तियां या पूर्व जज अथवा पूर्व आई ए एस एकजुट हुये या फिल्म जगत के लोग,लेखक,साहित्यकार आदि ने सत्ता की नाकामियां उजागर करने के लिये आवाजें उठाएँ उसी वक्त सत्ता ने भी इन्हीं वर्ग विशेष से सम्बद्ध अपने समर्थकों को खड़ा कर दिया। पिछली बार तो सत्ता को अपनी इन कोशिशों में उस समय शर्मिंदा भी होना पड़ा जबकि सत्ता के समर्थन में खड़े होने वाले कई तथाकथित 'विशिष्ट' लोगों के भ्रष्ट व काले कारनामों का रिकार्ड भी विपक्ष ने ढूँढकर सार्वजनिक कर दिया।

बहरहाल अफसोस यह है कि भाजपा की 'बांटो और राज करो ' की नीति की जद में अब साधु संत भी आ चुके हैं। जो भी संत भाजपा की किसी भी नीति की आलोचना करते हैं या एक संत के नाते शास्त्र सम्मत बातें करते हैं या कुछ ऐसी व्यवस्था देते हैं जो कि राजनैतिक होने के बजाये शुद्ध धार्मिक हो, उसे भाजपा सहन नहीं कर पाती। देश में अनेकानेक ऐसे योग्य संत हैं जो धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं वह भाजपा की सत्ता या उसके प्रभाव में कतई नहीं आते। परन्तु भाजपा की तो राजनीति ही धर्म के नाम पर चलती है। इसलिये भाजपा सत्ता समर्थक संतों को तरजीह देती है और उन्हें बढ़ावा भी देती है। उदाहरण के तौर पर सोशल मीडिया की 'कृपा ' से इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम चर्चा में है। दूसरों का भविष्य बताने वाले इस नवोदित संत ने कुछ वर्ष पूर्व ही सोशल मीडिया द्वारा 'अवतार' लिया है। इन्हें लोग 'बाबा बागेश्वर' या 'बागेश्वर धाम सरकार' के नाम से भी जानते हैं। वे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख हैं। शंकराचार्य स्तर के कई संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ज्योतिष विद्या और उनके 'पर्ची ' निकालने को ढोंग व शास्त्र विरोधी बता चुके हैं। परन्तु चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके 'हिन्दू राष्ट्र निर्माण मिशन ' के समर्थक हैं तथा उन्हें प्रधानमंत्री का संरक्षण हासिल है लिहाजा उनकी गिनती सत्ता के दुलारे संतों में की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की निकटता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी 2025 को बागेश्वर धाम का दौरा किया। यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी ही चतुराई से मोदी के गले में अपना नाम लिखा हुआ पटका तक डाल दिया। यहाँ मोदी ने एक कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री से इस 'घनिष्ट निकटता' के बाद अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को किसी वरिष्ठ संत या शंकराचार्य से किसी तरह का प्रमाण पत्र लेने की जरुरत ही क्या ?

मासूम की स्कूल से ले जाकर रिश्ते के चाचा ने कर दी हत्या, दुष्कर्म की आशंका

संवाददाता–देवरिया। जिले के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को रिश्ते के एक चाचा ने सात साल की मासूम बच्ची की स्कूल से ले जाकर हत्या कर दी और शव झरही नदी में फेंक दिया। बच्ची के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी बच्ची के पिता के सगे चाचा का लड़का है। पीडिघ्ता उसे बड़ा पापा कहकर बुलाती थी। मौके पर सीओ समेत कई पुलिस अधिकारी पहुंच कर छानबीन में जुटे हैं।

श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति की 7 साल की बेटी गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक की छात्रा थी। बुधवार की सुबह वह रोज की तरह स्कूल पढ़ने गई थी। दोपहर में लंच के बाद उसका चचेरा चाचा स्कूल पहुंचा और बच्ची को साइकिल से घर ले जाने की बात कहकर अपने साथ लेकर चला गया। इधर देर तक बच्ची के घर नहीं पहुंचने पर परिजन उसे ढूंढ़ने लगे। जब वह नहीं मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। उसी दौरान गांव से सट कर बहने वाली झरही नदी में कुछ ग्राामीणों ने बच्ची का शव देखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने नदी से शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। जांच में स्कूल के पास लगे सीसी कैमरे को खंगाला गया तो उसमें रिश्ते का चाचा बच्ची को लेकर जाते हुए दिखा। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। 35 वर्षीय आरोपी शादीशुदा और दो बच्चों का बाप है। वह पीड़िता के पिता के सगे चाचा का लड़का है। बच्ची उसे बड़ा पापा कहकर बुलाती थी। आरोपी नशे का भी आदी बताया जा रहा है। बच्ची के पिता बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने मामले का शीघ्र खुलासा कर आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक बच्ची का शव मिला है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर गहन जांच कर रही है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है कि नहीं यह पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अंशुमन श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी।

8 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

संवाददाता–महराजगंज। भारत–नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 किलो 13 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है। सोनौली बॉर्डर पर चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीम ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया।

बरामद मादक पदार्थ उच्च गुणवत्ता वाला हाइड्रोपोनिक वीड है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 7 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है। इसे सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, नियमित जांच के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर दो व्यक्तियों को रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से विशेष तकनीक से उगाया गया यह गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी महाराष्ट्र के निवासी हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वे थाईलैंड से नेपाल के काठमांडू होते हुए सोनौली बॉर्डर के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां इस तस्करी नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर लगातार चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के चलते मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है।

पढ़ाई में आर्थिक सहयोग न मिलने पर छोटे भाई ने की थी शिवशंकर की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

संवाददाता–गोंडा। कर्नलगंज के नरायनपुर माझा के दुल्हिनपुरवा निवासी शिवशंकर की हत्या का पुलिस ने राजफाश किया है। पुलिस का दावा है कि पढ़ाई में आर्थिक सहयोग न मिलने पर छोटे भाई अमरनाथ ने ही शिवशंकर की हत्या की थी। आरोपित को गांव के बाहर पक्की सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही से भुलावन यादव के खेत की मेड़ के पास से छिपाए गए 31 हजार 500 बरामद किए गए है। एसपी विनीत जायसवाल ने कहा कि तीन फरवरी की रात में शिवशंकर दुबे निवासी दुल्हिनपुरवा नरायनपुर माझा को अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू मारकर हत्या की थी। इसमें पांच आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा किया गया। जांच में मृतक के छोटे भाई अमरनाथ दुबे को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों ने पूछताछ में बताया गया कि उसने इंटरमीडिएट व स्नातक की शिक्षा इलाहाबाद में रहकर पूर्ण की थी।

वर्ष 2023 से 2025 तक दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अगस्त 2025 से लखनऊ में रहकर तैयारी कर रहा था। पढ़ाई के दौरान उसे परिवार से अपेक्षित आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा था, जिससे वह लगातार तनाव में रहने लगा। परिवार की आय–व्यय का पूरा नियंत्रण उसके बड़े भाई शिवशंकर दुबे के पास था।

आरोपित के मन में यह धारणा बन गई कि उसका भाई जानबूझकर उसे पैसे नहीं दे रहा है और उसके भविष्य व करियर को खराब कर रहा है। भाई के प्रति द्वेष रखने लगा। जब उसे जानकारी हुई कि उसके माता–पिता दो जनवरी को एक माह के लिए कल्पवास के लिए प्रयागराज जा रहे हैं, तब उसने मौका देखकर एक जनवरी को लखनऊ से घर आने का निर्णय लिया। घर आने के बाद उससे खेती–बाड़ी व पशुओं की देखभाल का कार्य कराया जाने लगा।

उसकी पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही थी और उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा था। उसके भाई के पास नकदी रहती है। तभी उसने भाई की हत्या कर रुपये लेने की योजना बनाई। 27 जनवरी को कस्बा कर्नलगंज बस स्टाप के पास साइकिल से चाकू बेचने वाले व्यक्ति से 60 रुपये में चाकू खरीदा। 31 जनवरी को पड़ोस की भाभी को बैंक ले जाने के दौरान उसने कर्नलगंज कस्बे में रामतेज बिल्डिंग की दुकान पर 20 रुपये देकर उसी चाकू की धार तेज कराई।

रात करीब 11 बजे उसने खेत में पानी लगाने का बहाना बनाया और अपने भाई को साथ लेकर घर से निकला। रास्ते में सुनसान स्थान पर पहुंचते ही उसने बड़े भाई पर मिर्च पाउडर झोंक दिया और चाकू से गले पर कई वार कर हत्या कर दी। मृतक की जेब से रुपये निकाले और खून लगा चाकू गेहूं के खेत में फेंक दिया। स्वयं को बचाने व शक से दूर रखने के लिए वह गांव की ओर भागते हुए शोर मचाने लगा कि उसके भाई को किसी ने मार दिया है। एसपी ने कहा कि आरोपित को जेल भेजा जा रहा है। राजफाश करने वाली टीम को 25 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है।

अमिताभ ठाकुर से जेल में मिले आजाद अधिकार सेना पदाधिकारी, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

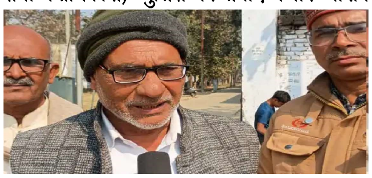

संवाददाता–देवरिया। जिला कारागार में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर से बुधवार को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद पांडे और युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने मुलाकात की। करीब आधे घंटे चली इस मुलाकात में संगठनात्मक गतिविधियों और वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा हुई।

मुलाकात के बाद जेल से बाहर आए विनोद पांडे ने मीडिया से बातचीत में लखनऊ पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि लखनऊ पुलिस देवरिया में डेरा डाले हुए है और अमिताभ ठाकुर को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती। पांडे के अनुसार, पुलिस फर्जी मुकदमों के जरिए उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, जिसका आजाद अधिकार सेना हर स्तर पर विरोध करेगी।

विनोद पांडे ने यह भी कहा कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान अमिताभ ठाकुर ने संगठन को मजबूत करने, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को तेज करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के निर्देश दिए।

प्रदेश अध्यक्ष ने जिला प्रशासन से यह भी सवाल किया कि लखनऊ पुलिस की टीम देवरिया में किस उद्देश्य से मौजूद है, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी को लखनऊ में दर्ज एक मुकदमे में अमिताभ ठाकुर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है, और न्यायालय से राहत मिलने के बावजूद पुलिस की सक्रियता चिंताजनक है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रोडमैप है बजट में -पंकज चौधरी

संवाददाता–महराजगंज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य के सर्वांगीण विकास और समृद्धि को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रावधानों की घोषणा की है। सरकार के अनुसार वर्ष 2024–25 के त्वरित अनुमान में प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़कर 30.25 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वहीं लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर लाने और बेरोजगारी दर को घटाकर 2.24 प्रतिशत तक लाने का भी दावा किया गया है। यह बजट विकास, विश्वास और समृद्धि की भावना से तैयार किया गया है और प्रदेश को नई आर्थिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रोडमैप प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के समन्वय का सकारात्मक परिणाम अब प्रदेश की प्रगति के रूप में दिखाई दे रहा है। पंकज चौधरी ने कहा कि बजट में गांव, गरीब,

किसान, नौजवान और महिलाओं को केंद्र में रखकर सर्वस्पर्शी और संतुलित प्रावधान किए गए हैं। कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, फसल उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजनाओं को गति दी गई है। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजन के नए अवसर पैदा करने की दिशा में ठोस पहल की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार और युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने के प्रयास प्रदेश के भविष्य को मजबूत बनाएंगे, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, नए अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं के विकास से आमजन को बेहतर उपचार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी और शहरी विकास जैसे बुनियादी ढांचे पर निवेश से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि मोदी सरकार और योगी सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संकल्प के साथ प्रस्तुत यह बजट उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समाज के हर वर्ग के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा।

बजट को व्यापारियों ने सराहा

संवाददाता–बहराइच। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, लघु उद्योग को बढ़ावा देने के साथ ही महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगों के लिए केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। इसी के तहत बहराइच जनपद में भी वूमेन वर्किंग हॉस्टल की स्थापना होगी और सड़कों की दशा में सुधार होगा। बजट को लेकर नेताओं और व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं।

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष मनीष मल्होत्रा ने कहा कि यह बजट विकासोन्मुख है और व्यापारियों के हितों को मजबूती देने वाला है। उन्होंने इसे श्आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेशश के एजेंडे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

मल्होत्रा ने कहा कि 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य व्यापारियों और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च से व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद जताई। वहीं, कैसरगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक आनंद यादव ने इस बजट को श्छलावाश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें कमजोरों और गरीबों का ख्याल नहीं रखा गया है।

वशिष्ठ रामायण कथा का रामलला को मिला निमंत्रण

गुरु–शिष्य परंपरा को जीवंत रखने का प्रयास –राणा दिनेश प्रताप सिंह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या।भगवान श्रीराम को उनके सेवक एवं परिवार सहित बस्ती स्थित पौराणिक वशिष्ठ पीठ आश्रम में आयोजित होने वाली 'वशिष्ठ रामायण' कथा के लिए विधिवत आमंत्रित करने हेतु बुधवार को अयोध्या में भव्य आयोजन हुआ। कारसेवक पुरम से निकले विशाल जुलूस के साथ हजारों श्रद्धालु श्रीराम जन्मभूमि परिसर पहुंचे और रामलला के दर्शन कर उन्हें आमंत्रण अर्पित किया। इसके उपरांत श्रद्धालु हनुमानगढ़ी पहुंचे और हनुमानजी महाराज को भी इस महापर्व में पधारने का निमंत्रण दिया।यह धार्मिक आयोजन बस्ती जनपद के बढ़नी मिश्र पौराणिक वशिष्ठ पीठ आश्रम में 18 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। कथा का वाचन तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के मुखारविंद से किया जाएगा।

कार्यक्रम के संयोजक राणा दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि बस्ती ने भगवान श्री राम को दुनिया को दिया और उनके त्रेता युग के गुरु आश्रम में वशिष्ठ जी विराजमान होने जा रहे है, ऐसे में हम लोग गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत करने के लिए प्रभु श्री राम को परिवार सहित और हनुमान जी महाराज को इस महापर्व में जो 18 फरवरी से 26 फरवरी तक गुरु वशिष्ट के आश्रम में चलेगा जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज कथा कहेंगे उसमें आमंत्रित करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल बस्ती ही नहीं, बल्कि समूची अयोध्या और प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए गौरव का अवसर है। कार्यक्रम में अध्यक्ष सतीश कुमार मिश्रा, मुख्य यजमान चंद्रभूषण मिश्रा, रत्नेश कुमार मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। श्रद्धालुओं ने जय श्रीराम के उद्घोष के साथ भक्ति–भाव से आमंत्रण यात्रा संपन्न की।आयोजकों ने समस्त अयोध्यावासियों एवं प्रदेशवासियों से इस महान अनुष्ठान में सहभागिता का आह्वान किया है।

38 ग्रामों की विकास योजनाओं को मिली मंजूरीः डीएम ने की बैठक, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत दिए निर्देश

संवाददाता–बहराइच। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जनपद में चयनित 38 ग्रामों की विकास योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया। जिलाधिकारी ने अनुमोदित प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा विकसित पीएम–अजय पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था नामित ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2025–26 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का अंतिम वर्ष है। इसलिए, चयनित कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक चयनित ग्राम में 20–20 लाख रुपये की धनराशि से विभिन्न अवसंरचनात्मक कार्य कराए जाएंगे। इनमें नाली निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर हाई मास्ट लाइट, सोंक पिट, कम्पोस्ट पिट, इंडिया मार्का हैंडपंप, आंगनबाड़ी निर्माण और आरसीसी निर्मित छोटी पुलिया शामिल हैं। इन कार्यों को शासन द्वारा निर्धारित मानक और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा।

जिलाधिकारी त्रिपाठी ने एडीओ समाज कल्याण को प्रस्तावित कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले गांवों का सर्वांगीण विकास करना है, ताकि सभी मूलभूत सुविधाओं का विकास कर लक्षित वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

जिलाधिकारी ने पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, आईसीडीएस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, विद्युत, खाद्य एवं रसद, लघु सिंचाई, कौशल विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और बैंकिंग सहित विभिन्न विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लक्षित पात्र 19295 व्यक्तियों को शीघ्रता से विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।

बैठक का संचालन करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रद्धा पाण्डेय ने बताया कि केन्द्र प्रायोजित अनुसूचित जाति सब–प्लान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के घटक आदर्श ग्राम के अन्तर्गत जनपद में अनुसूचित जाति बाहुल्य ऐसे 38 ग्रामों जहां पर अनुसूचित जाति की आबादी 40 प्रतिशत अधिक है, का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजय कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रद्धा पाण्डेय, जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय, जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वदानन्द, जिला कार्याक्रम अधिकारी निहारिका विश्वकर्मा, लीड बैंक प्रबन्धक जितेन्द्र मंसद सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी तथा एडीओ समाज कल्याण मौजूद रहे।

आइसक्रीम फैक्ट्री में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से 10 लाख से अधिक का नुकसान

संवाददाता–देवरिया। जिले के स्टेशन रोड स्थित एक आइसक्रीम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिससे फैक्ट्री में रखा 10 लाख रुपये से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि, इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

सदर कोतवाली क्षेत्र के सोमनाथ नगर मोहल्ला निवासी अशोक मद्धेशिया की स्टेशन रोड पर यह आइसक्रीम फैक्ट्री संचालित है। फैक्ट्री में लगभग एक दर्जन मजदूर कार्यरत हैं। बताया गया कि लग्न के मौसम को देखते हुए मजदूर आइसक्रीम तैयार करने में जुटे थे, तभी अचानक विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया।

आग लगने के बाद आसपास के लोगों ने शुरुआती तौर पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एहतियात के तौर पर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी, जिससे किसी बड़े हादसे को टाला जा सका।

फैक्ट्री संचालक अशोक मद्धेशिया के अनुसार, आग से गोदाम में रखी मशीनें, फ्रीजर, कच्चा माल और तैयार आइसक्रीम सहित लगभग 10 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है

10वें बजट में श्रावस्ती के विकास, शिक्षा–स्वास्थ्य पर खास ध्यान

संवाददाता–श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना 10वां बजट सदन में पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत इस बजट में प्रदेश के समग्र विकास के साथ–साथ श्रावस्ती जनपद को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसमें बाढ़ नियंत्रण, प्रशासनिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण और पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

बजट में श्रावस्ती में बाढ़ शमन योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या से राहत दिलाना है। इसके अलावा, बलरामपुर–श्रावस्ती को बौद्ध सर्किट से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रशासनिक भवन एवं अन्य निर्माणाधीन संरचनाओं का कार्य भी प्रगति पर है।

इस वर्ष प्रस्तुत 53.47 लाख करोड़ रुपये का यह बजट श्मेक इन इंडियाश और श्आत्मनिर्भर भारतश जैसी योजनाओं को गति देने की महत्वाकांक्षी रूपरेखा के रूप में देखा जा रहा है।

वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे और परिवहन नेटवर्क पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, सड़क एवं राजमार्ग, गृह तथा रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताएं तय की गई हैं।

श्रावस्ती को रेल लाइन से जोड़ने की दिशा में भी बजट में ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वूमेन हॉस्टल स्थापित करने तथा प्रमुख एवं छोटे तीर्थ स्थलों के विकास की योजनाएं भी इसमें शामिल हैं।

बजट में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को वैश्विक केंद्र बनाने, कैंसर की दवाओं को सस्ता करने, बायो–फार्मा योजना की शुरुआत, उद्योगों को प्रोत्साहन, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, श्लखपति दीदीश और श्गांव की दीदीश जैसी योजनाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया है। साथ ही, माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार, गरीबी उन्मूलन, पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। कुल मिलाकर, यह बजट प्रदेश के समग्र विकास के साथ–साथ श्रावस्ती जैसे पिछड़े जनपदों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बिट्रिश मौलाना के आवास पर ईडी ने मारा छापा

संवाददाता–संतकबीरनगर। दुधारा थाना क्षेत्र के देवरियालाल गांव निवासी ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान के खलीलाबाद शहर स्थित मीट मंडी रोड स्थित आवास रजा मंजिल पर लखनऊ की ईडी जोनल टीम बुधवार को भोर में करीब सुबह चार बजे छापा मारा। घर पर मौलाना का बेटा नहीं मिला, जबकि मौलाना की पत्नी व बहू घर पर मौजूद थीं, जिनसे ईडी की टीम जांच पड़ताल व पूछताछ कर रही है।

घर के बाहर सीआरपीएफ का पहरा लगा हुआ है और किसी को अंदर जाने व अंदर से बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं, दूसरी ओर ईडी की एक टीम आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर स्थित मिल्लतनगर मोहल्ला में भी छानबीन कर रही है। खलीलाबाद शहर में ईडी की टीम मंगलवार को ही आ गई थी। सूत्रों की मानें तो एक टीम दिन में ही पहुंचकर मौलाना शमशुल हुदा के घर व आसपास की स्थित को जान लिया था। मोहल्ले में लखनऊ नंबर की वीआईपी लिखी गाड़ी घूमती हुई देखी गई थी। वहीं, बुधवार को तीन अन्य गाड़ियों में ईडी के अधिकारी व सीआरपी की टीम खलीलाबाद पहुंची। इसके बाद ईडी की टीम मौलाना के घर में दाखिल हुई और अपनी जांच पड़ताल शुरु कर दी। वहीं सीआरपी के जवान घर के बाहर मुस्तैद हो गए।

बाहरी व्यक्ति को घर के अंदर जाने के लिए प्रवेश वर्जित कर दिया। दिन में कई बार गोला चौकी पुलिस भी घर के आसपास पहुंचकर स्थिति का आंकलन व शांति व्यवस्था की निगरानी की। स्थानीय पुलिस को पहले ही उच्चाधिकारियों की तरफ से ईडी की जांच व मौके पर शांति व्यवस्था में सहयोग के लिए निर्देश दे दिया गया था।

खलीलाबाद कोतवाली में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मित्र के पेश के तहत दर्ज कराई गई रिपोर्ट की विवेचना चल रही है। दिन में करीब दो बजे के आसपास केस के विवेचक ललितकांत यादव भी अभिलेखों के साथ मौलाना के आवास रजा मंजिल पर ईडी का जांच में सहयोग के लिए पहुंचे। वह घर के भीतर दाखिल हुए और लगभग आधा घंटा से ज्यादा का समय जांच टीम के साथ व्यतीत किया। इसके बाद वह निकलकर वहां से चले गए। मौलाना शमशुल हुदा खान के तीन बैंक में सात एनआरआई व एनआरओ खाते की पुष्टि हुई थी। जांच से जुड़े सूत्रों की मानें तो एसबीआई बैंक से किसी भी तरह के विदेशी फंडिग की सूचना नहीं मिल सकी, जबकि एचडीएफसी व बैंक ऑफ बड़ौदा खाते में लगभग 25 लाख रुपये विदेश से आने की पुष्टि हुई है और एसबीआई बैंक से जांच टीम को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान के खिलाफ फेमा के तहत रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी ने उसका व परिवार के सदस्यों का विभिन्न बैंक में 18 खाता को फ्रीज करा दिया। इसके साथ ही उक्त सभी खातों में मौजूद लगभग एक करोड़ रुपये के निकासी पर भी रोक लगा दिया गया। अब जांच टीम की निगाह मौलाना के रजा फाउंडेशन व कुल्लियतुल बनातिर रजविया एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के बैंक खातों पर निगाह टिक गई है। इसकी जांच के बाद भी कंफर्म होगा कि किन–किन देशों से कितना रकम सोसाइटी के खाते में आया।

प्रेमिका से मिलने गया प्रेमी, लोगों ने पकड़कर करा दी शादी

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। प्रेम प्रसंग का अनोखा घटनाक्रम सामने आया है। नगर पंचायत बिस्कोहर के बेलवा गांव में मंगलवार को प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से गांव में ही हिंदू रीति–रिवाज के साथ विवाह संपन्न करा दिया गया। घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार इटवा थाना क्षेत्र के ग्राम दुफेड़िया निवासी दिनेश का त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवा निवासी आशा से काफी समय से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों बालिग बताए गए हैं। मंगलवार को युवक चुपके से प्रेमिका से मिलने उसके गांव के सीवान में पहुंचा। इसकी भनक कुछ ग्रामीणों को लगी तो वे मौके पर पहुंच गए और दोनों को पकड़ लिया।

ग्रामीणों ने दोनों को गांव लाकर परिजनों को सूचना दी। शुरुआत में कुछ देर तक नोकझोंक और असहमति की स्थिति रही, लेकिन बाद में दोनों परिवारों के बीच सहमति बन गई। पंचायतनुमा माहौल में विवाह कराने का निर्णय लिया गया। इसके बाद गांव के लोगों की मौजूदगी में वर–वधू ने एक–दूसरे को वरमाला पहनाई। मिठाई खिलाकर विवाह की रस्में पूरी की गईं। बताया जाता है कि कुछ लोगों की उपस्थिति में लिखित सहमति पत्र भी तैयार किया गया। इसके बाद युवती को विधिवत विदा कर युवक के साथ भेज दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि आपसी सहमति और सामाजिक पहल से मामला सुलझा लिया गया, जिससे अनावश्यक विवाद और कानूनी प्रक्रिया से बचाव हुआ। गांव में दिनभर इस घटना की चर्चा होती रही।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय सदर बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0– /23
शिववरन
बनाम
सरकार उ0प्र0
1. सोनू पुत्र भगवान दास साकिन कुदरहा तप्पा कुदरहा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 25–02–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 25 माह 02 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान चतुर्थ अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
इजरा वाद सं0–03/1995
रामशंकर
बनाम
फेरई
1. जलाल उर्फ ठाकुर प्रसाद पुत्र फेरई 2. वंशीधर पुत्र बाबूलाल साकिनान सरैया तिवारी तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती
तारीख पेशी 11–03–2026

हरगाह मुद्दई मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश हाजा बस्व हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 11 माह 03 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

शिक्षकों ने केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी के विरोध में निकाला जुलूस, फूंका पुतला

संवाददाता–संतकबीरनगर। जिले में बुधवार की शाम प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के विरोध में जुलूस निकाला। डीएम कार्यालय के सामने पुतला फूंका। शिक्षकों का यह प्रदर्शन जयंत चौधरी द्वारा टेट की अनिवार्यता के सम्बन्ध में जारी किए गए पत्र के विरोध में किया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनपद के नौ ब्लॉक के शिक्षक बुधवार की शाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एकत्र हुए। जिला अध्यक्ष अंबिका देवी, विजय नाथ यादव, के सी सिंह के नेतृत्व में जनपद के शिक्षकों ने जुलूस निकाला। जयंत चौधरी का हाथों में पुतला लेकर टेट की अनिवार्यता समाप्त करने, शिक्षक एकता जिंदाबाद, केंद्रीय मंत्री मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए डीएम कार्यालय पर पहुंचे।

जमकर नारेबाजी करते केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का पुतला फूंका। मौके पर पुलिस मौजूद रही। शिक्षक केंद्रीय मंत्री के टेट के बारे में जारी पत्र के विरोध आक्रोशित दिखे। टेट की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की। कहा कि यह शिक्षकों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जनपद के बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान चतुर्थ अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–1009/94
श्रीमती अनारी आदि
बनाम
ओम प्रकाश आदि
2/2 विकास गोस्वामी पुत्र दुर्गा 2/4 शिवसरन पुत्र रामजन्म गोस्वामी साकिन धनघटा तप्पा महथी परगना महुली पूरब तहसील धनघटा जिला संतकबीरनगर
तारीख पेशी 26–02–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 26 माह 02 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख 11 माह 02 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

ग्रामीणों में चकबंदी को लेकर है काफी आक्रोश

संवाददाता–संतकबीरनगर। जिले के संठी गांव के किसानों में चकबंदी को लेकर काफी आक्रोश है। किसान प्रभुनाथ की मौत के बाद लेखपाल व एसीओ के निलंब के बाद भी आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों का आरोप है कि पिछले दो वर्षों से हो रही चकबंदी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया। चक आवंटन, हिस्सेदारी तय कराने, नाम दर्ज कराने और आपत्तियों के निस्तारण के नाम पर लेखपाल से लेकर जिला स्तर तक खुलेआम धन उगाही होती रही। जो किसान पैसे देने में सक्षम रहे, उनके काम आसानी से हो गए, जबकि गरीब और ईमानदार किसानों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े।ग्रामीणों का आरोप है कि कई मामलों में एक पक्ष से पैसा लेने के बाद दूसरे पक्ष से अधिक रकम लेकर चक आवंटन जान बूझ कर इधर–उधर कर दिया गया। तरमीन (मूल्यांकन) और मालियत (उपज क्षमता) निर्धारण में भी खुला खेल खेला गया। पैसे देने वाले किसानों के खेतों की मालियत बढ़ा दी गई, जबकि ईमानदार किसानों के खेतों की मालियत घटाकर उन्हें नुकसान में डाल दिया गया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि गांव में कुछ स्थानीय दलालों का पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया, जो दोनों पक्षों से पैसा वसूलकर चकबंदी अधिकारियों तक पहुंचाते थे। तकनीकी जाल इतना उलझा हुआ था कि कई किसान समय रहते इसे समझ नहीं पाए और चक आवंटन के बाद रकबा घटने–बढ़ने की सच्चाई सामने आने पर वे ठगे रह गए। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए दो टूक कार्रवाई की मांग की।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपाण्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्रर्रह समायत अपील
प्रकीर्ण सिविल अपील सं0–80/2025
अदालत– श्रीमान जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती
पंचम वर्मा आदि
बनाम
पल्टू आदि
1. पल्टू उम्र लगभग 43 साल पुत्र चैतू 2. चैतू उम्र लगभग 68 साल पुत्र अदालत 3. लौटू उम्र लगभग 40 साल पुत्र चैतू 4. कन्हैया उम्र लगभग 25 साल पुत्र चैतू 5. किशन उम्र लगभग 22 साल पुत्र चैतू साकिनान मौजा अरजानीपुर तप्पा बनगवा पोस्ट परसरामपुर परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती
–रेस्पाण्डेण्ट/प्रतिवादीगण
तारीख पेशी 06–03–2026
अपील बनराजी के अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पाण्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 06 महीना 03 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय सदर बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0– /23
शिववरन
बनाम
सरकार उ0प्र0
1. सरोजा देवी पत्नी रामजग साकिन कुदरहा तप्पा कुदरहा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 25–02–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 25 माह 02 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय सदर बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0– /23
शिववरन
बनाम
सरकार उ0प्र0
1. जितेन्द्र कुमार पुत्र रामपियारे साकिन कुदरहा तप्पा कुदरहा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 25–02–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 25 माह 02 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–366/2008
रामअवध
बनाम
हरिद्वार आदि
1/1/1 राज कुमार उम्र लगभग 40 वर्ष 1/1/2 रीतेश उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्रगण रामललित 1/1/3 नरायनदेई पत्नी स्व0 रामललित उम्र 64 वर्ष 1/2 बलराम उम्र लगभग 65 वर्ष पुत्र हरिद्वार साकिनान मौजा पाकरडाड तप्पा कपरी महसो परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 18–03–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 18 माह 03 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

विदेश भेजने के लिए 89 हजार हड़पे, केस दर्ज

संवाददाता–गोरखपुर। विदेश भेजने के नाम पर 89 हजार रुपये की जालसाजी करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। चौरीचौरा थानाक्षेत्र के देवकहिया निवासी बाबूलाल ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनका पुत्र जय हिंद रोजगार के सिलसिले में विदेश जाना चाहता था। उसका परिचय किरण कुमार से हुआ तो उसने बताया कि गगहा थानाक्षेत्र के ग्राम मुसौली निवासी अफरोज विदेश भेजने का काम करता है। जब अफरोज से मुलाकात हुई तो बताया कि उसके पास वर्ल्ड स्टार कंपनी दुबई में वाल पेंटर का वीजा है। इसमें सैलरी सोलह सौ दरहम है। विश्वास में लेकर उसने 89 हजार रुपये ले लिए।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय सदर बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0– /23
शिववरन
बनाम
सरकार उ0प्र0
1. प्रेमसागर पुत्र राममिलन साकिन कुदरहा तप्पा कुदरहा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 25–02–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 25 माह 02 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय सदर बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0– /23
शिववरन
बनाम
सरकार उ0प्र0
1. जयद्रथ पुत्र रामलौट साकिन कुदरहा तप्पा कुदरहा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 25–02–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 25 माह 02 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

प्रारूप 7
(देखे नियम–11 (1)
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना
अदालत–श्रीमान जे0एम0/ एफ0 टी0 सी0 (सी0ए0डब्लू0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्ण घरेलू हिंसा परिवाद वाद सं0 501/2025
थाना–कोतवाली
जिला–बस्ती
श्रीमती खालिदा खातून आदि
बनाम
मकसूद अहमद आदि
1. मकसूद अहमद उम्र तख्मीनन 38 साल पेशा ठेकेदार (पति) 2. शमशाद उम्र तख्मीनन 35 साल पेशा जे0सी0बी0 चाकल (देवर) पिसरान महमूदुल हसन खां 3. महमूदुल हसन खां उम्र तख्मीनन 60 साल पिसर मोहम्मद शफात पेशा लकड़हारा (ससुर) 4. श्रीमती असीमुन्निशा उम्र तख्मीनन 35 साल जौजे महमूदुल हसन खां पेशा गृहणी (सास) 5. कु0 सायरा खातून उम्र तख्मीनन 24 साल दुख्तर महमूदुल हसन खां पेशा विद्यार्थी (ननद) साकिनान ग्राम दुलहापार कला पो0 पौली थाना धनघटा जिला संतकबीरनगर पिन कोड 272162 6. श्रीमती ताहिरा खातून उम्र तख्मीनन 30 साल जौजे अजमल दुख्तर महमूदुल हसन खां ग्राम वो पो0 पौली थाना धनघटा जिला संतकबीर नगर पेशा गृहणी (ननद) पिन कोड 272162 7. श्रीमती राबिया खातून दुख्तर महमूदुल हसन खां जौजे शमशुद्दीन ग्राम दहेलवा पो0 बभनान थाना परशुरामपुर जिला बस्ती पेशा गृहणी (ननद) पिन कोड 272161
–विपक्षीगण
तारीख पेशी 25–02–2026

याची ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा– 12 के अधीन आवेदन फाइल किया है/किये है। आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदक द्वारा मांगे गये (अनुतोषों) को आपके विरूद्ध प्रदान कर दिया जाय व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत काउन्सेल के मार्फत तारीख 25 मास 02 सन् 2026 को बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। इसमे असफल होने पर न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही करेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख को दी गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान चतुर्थ अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–377/2021
ब्रम्हदेव आदि
बनाम
फूलचन्द आदि
4/1 अजय कुमार आयु करीब 50 साल 4/2 अभय कुमार आयु करीब 42 साल 4/3 विजय कुमार आयु करीब 47 साल पुत्रगण स्व0 श्री मनोहरलाल 4/4 लक्ष्मी आयु करीब 70 साल विधवा मनोहर लाल निवासी ग्राम पिकौरालाला तप्पा सिकन्दरपुर परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती 2/1 आयुष वर्मा आयु करीब 12 साल 2/2 सचिन वर्मा आयु करीब 10 साल नावालिगान पुत्रगण गंगाराम पत्नी तुलसी माता हकीकी 2/3 सन्जू वर्मा आयु करीब 15 साल 2/4 मन्जू वर्मा आयु करीब 14 साल नावालिगान पुत्रीगण गंगाराम वलायत तुलसी माता हकीकी 2/5 तुलसी आयु करीब 40 साल पत्नी स्व0 गंगाराम निवासीगण ग्राम पिकौरालाला तप्पा सिकन्दरपुर परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती
तारीख पेशी 16–02–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 16 माह 02 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

युवती का पांच दिन बाद शारदा बड़ी नहर में मिला शव

संवाददाता–अयोध्या। महाराजगंज थाना क्षेत्र के बिल्हार घाट बड़ी नहर में कूदकर लापता हुई युवती का शव पांच दिन बाद शारदा बड़ी नहर में बरामद हुआ। पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को कब्जे में लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 6 फरवरी को पीआरवी 0916 को समय लगभग 3रू52 बजे कॉलर शुभम विश्वकर्मा द्वारा सूचना दी गई कि बिल्हार घाट बड़ी नहर में एक महिला का शव दिखाई दिया है। सूचना पर पीआरवी टीम तत्काल मौके पर पहुंची। संबंधित पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच–पड़ताल की। तहकीकात में पता चला कि सविता गौड़ उर्फ चुलबुली (20), पुत्री स्वर्गीय कृष्णदेई, निवासी ग्राम गोविंदपुर मजरे खानपुर, थाना महाराजगंज, किसी पारिवारिक विवाद के चलते नाराज होकर घर से निकल गई थीं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती ने अपनी चप्पल और मोबाइल पुल पर रखकर नहर में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन वह गहरे पानी में डूब गई। घटना के बाद से लगातार शव की तलाश की जा रही थी। बुधवार सुबह घटना के छठे दिन घटनास्थल से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूरी पर ग्रामीणों ने शारदा बड़ी नहर के ग्राम दतौली के पास एक शव को बहते हुए देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। मृतका की पहचान उसके भाई उमेश द्वारा सविता गौड़ के रूप में की गई। थाना अध्यक्ष महाराजगंज राजेश सिंह ने बताया कि पंचायतनामा सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था सामान्य है और किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति नहीं है।

नवजात शिशु अपहरण का 8वां आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता–संतकबीरनगर। पुलिस ने नवजात शिशु अपहरण मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। बेलहरकला थाना पुलिस ने इस मामले के आठवें आरोपी जोगी उर्फ योगेन्द्र बारी को 11 फरवरी 2026 को नरायनपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यह मामला 9 फरवरी 2026 को बेलहरकला थाने में दर्ज किया गया था। वादिनी ने शिकायत की थी कि अज्ञात अभियुक्तों ने उसकी गोद से लगभग एक माह के नवजात शिशु को छीनकर जंगल की ओर भाग गए थे। इस शिकायत के आधार पर थाना बेलहरकला में धारा 140(1), 143(4), 3(5) बीएनएस के तहत अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जोगी उर्फ योगेन्द्र बारी पुत्र रमेश बारी निवासी छितौना, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर के रूप में हुई है।

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्मुखी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच, कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com